कालीनों का निर्यात

1341. **डा. रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात किये गये कालीनों की संख्या और मूल्य कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कालीन के निर्यात में हाल में गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कालीनों के निर्यातों के आंकड़े मीटरों में रखे जाते हैं और आंकड़े केवल 1982-83 तक के उपलब्ध हैं । आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं ।

वर्ष	मात्रा लाख वर्ग मीटर में
1980-81	46.4
1981-82	49.1
1982-83	50.3

गत तीन वर्ष के दौरान उनी कालीनों के निर्यातों का अनन्तिम मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :--

वर्ष	मूल्य करोड़ रु. में
1983-84	147.7
1984-85	157.6
1985-86	159.9

(ख) जी, नहीं ।

(ग) हांलाकि कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं ।

(1) उच्च मूल्य वर्धित कालीनों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कालीनों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है ।

(2) ऐसे मामलों में जहां कालीनों का एफ. ओ. बी. मूल्य 650/-रु. प्रति वर्ग मीटर से अधिक है, नकद मुआवजा सहायता को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) एफ. ओ. बी. मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से शुल्क वापसी की अनुमति दी गई है ।

(4) आर. ई. पी के आधार पर उन के शुल्क मुक्त आयात की योजना को उदार बनाया गया है ।

(5) उन के आयात पर शुल्क को मार्च, 1986 से 40 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

कालीनों का उत्पादन

1342. **डा. रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कालीनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इन में से कितने मूल्य के कालीन स्वदेशी बाजार में बेचे गए ;

(ग) कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया गया ;

(घ) कितने मूल्य के कालीन भंडारों में रखे हुए हैं ; और

(ङ) कालीन बुनकरों के हित में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस उद्योग का व्यापक रूप से दूर दूर तक फैले होने तथा पूर्णतः विकेन्द्रीकृत होने के कारण कालीनों के उत्पादन के संबंध में कोई पूरा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, मोटे तौर पर लगाए गए अनुमान के आधार पर उत्पादन जो 1980-81 में 170 करोड़ रु. का हुआ था बढ़कर 1985-86 में 210 करोड़ रु. का हो गया ।

(ख) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । साधारणतया यह अनुमान होता है कि उत्पादन का 10-15 प्रतिशत घरेलू बाजार में बिकता है ।

(ग) देश में निर्यात किए गए कालीनों के अन्तिम मूल्य आगे दिए गए हैं:--

वर्ष	मूल्य लाख रु. में
1983-84	147.7
1984-85	157.6
1985-86	159.9

(घ) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार कालीन बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सरकारी भंडारों में लगभग 2.30 करोड़ रु. मूल्य के कालीन रखे हुए थे। निजी भंडारों के संबंध में कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते।

(ङ) उठाए जा रहे कदम नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) व्यापक प्रशिक्षण के अलावा अधिक गांठों वाले कालीनों की बुनाई में उच्च प्रशिक्षण ;

(2) करघा पश्चात कार्यों जैसे किलपिंग, वाशिंग और फिनिशिंग में प्रशिक्षण ;

(3) भदोई (उ. प्र.) में कालीन प्रौद्योगिकी के लिए एक संस्थान की स्थापना करना ;

(4) उनके आयातों पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करना तथा निर्यातों के आधार पर उनके शुल्क मुक्त आयात का उदारीकरण ताकि देश में उन की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके ;

(5) उन का उत्पादन करने वाले राज्यों से उन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी बिहार राज्य की परियोजनाएं

1343. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य की कितनी परियोजनाएं अभी तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत हो जाने की आशा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक टसर विकास परियोजना भेजी है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने हाल ही में इस परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की है और इस समय उसमें संशोधन हो रहा है। तत्पश्चात इसे विचार के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

1344. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत समय से न तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का नामांकन किया गया है और न ही बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ; यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण से केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनेक परियोजनाएं आसाम, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से हटाये जाने के पश्चात् से इसके कर्मचारी परेशानी अनुभव कर रहे हैं तथा इससे बोर्ड का कार्य भी बहुत पिछड़ रहा है ; और

(घ) क्या इसके साथ-साथ मूंगा रेशम का उत्पादन बंद होने जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में मलबरी रेशम का प्रसार कार्य बंद पड़ा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 9 जुलाई, 1985 को पुनर्गठन किया गया है। अध्यक्ष के पद को भरने संबंधी मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) से (घ) जी नहीं।